



अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष
सहकारी समितियाँ एक बेहतर
दुनिया का निर्माण करती हैं

मध्यप्रदेश सहकारी समाचार



मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल का प्रकाशन

Website : www.mpscu.in
E-mail : rajyasanghbp@gmail.com

हिन्दी/पाक्षिक

प्रकाशन दिनांक 16 जनवरी, 2026, डिस्पैच दिनांक 16 जनवरी, 2026

वर्ष 69 | अंक 16 | भोपाल | 16 जनवरी, 2026 | पृष्ठ 8 | एक प्रति 7 रु. | वार्षिक शुल्क 150/- | आजीवन शुल्क 1500/-

कृषक कल्याण वर्ष में किसानों का करेंगे समग्र कल्याण : मुख्यमंत्री



भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश के किसानों के लिए वर्ष 2026 नई उम्मीदों और नए अवसरों का वर्ष होगा। किसान हमारे अन्नदाता हैं, जो अपने परिश्रम से देश और समाज का उदर-पोषण करते हैं। किसानों को आत्मनिर्भर बनाकर उनकी समृद्धि सुनिश्चित करना ही सरकार का एकमात्र ध्येय है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने रविवार को भोपाल के जंबूरी मैदान में आयोजित विशाल किसान सम्मेलन में वर्ष 2026 को "कृषक कल्याण वर्ष" के रूप में मनाने की अधिकृत घोषणा की।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए हर जरूरी कदम उठाएगी। आधुनिक तकनीक, उन्नत बीज, सिंचाई, भंडारण और बाजार तक बेहतर पहुंच के माध्यम से खेती को लाभ का व्यवसाय बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कृषि केवल आजीविका का एक साधन ही नहीं, बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। कृषि क्षेत्र के सशक्तिकरण में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने किसान सम्मेलन के दौरान ई-विकास, वितरण एवं कृषि उर्वरक आपूर्ति समाधान प्रणाली (विकास पोर्टल) का शुभारंभ किया। कृषक कल्याण वर्ष 2026 में किसानों की आमदनी बढ़ाने सहित इनकी बेहतरी और खुशहाली के लिए किए जाने वाले प्रयासों के संबंध में एक लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया। किसान सम्मेलन में सरकार की विभिन्न योजनाओं, नवाचारों और भावी कार्ययोजना की जानकारी भी किसानों को दी गई।

पूरा साल किसानों के कल्याण के लिए समर्पित

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने पूरा साल किसानों के कल्याण के लिए



समर्पित किया है। हमारी सरकार खेतों से निकलने वाली पराली से भी किसानों आय बढ़ाने का प्रयास करेगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि हमारा मध्यप्रदेश देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां बीते सालों के प्रयासों से खेती का रकबा ढाई लाख हेक्टेयर तक बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में पार्वती - कालीसिंध - चंबल (पीकेसी) नदी लिंक एवं केन-बेतवा नदी लिंक राष्ट्रीय परियोजना सहित तामी ग्राउंड वाटर रिचार्ज मेगा परियोजना से प्रदेश के 25 जिलों में 16 लाख हेक्टेयर से अधिक अतिरिक्त कृषि रकबा सिंचित हो जाएगा। किसानों के हित में हमने जा कहा, वह करके दिखाया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि किसानों के हित में हमने जो कहा, वह करके दिखाया है। प्रदेश में श्रीअन्न उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए डिण्डोरी जिले में मध्यप्रदेश राज्य श्रीअन्न अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाएगी। इससे श्रीअन्न का उत्पादन और पोषण सुरक्षा को नई ऊंचाई मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि खालियर में सरसों अनुसंधान और उज्जैन में चना अनुसंधान केंद्र स्थापित किए जा रहा है। इन केंद्रों के जरिए इन फसलों की गुणवत्ता और पैदावार बढ़ाने पर विशेष बल दिया जाएगा। मुख्यमंत्री

डॉ. यादव ने कहा कि हम प्रदेश के 30 लाख से अधिक किसानों को अगले तीन साल में सोलर पावर पम्प देंगे। हर साल 10 लाख किसानों को सोलर पम्प देकर इन्हें अन्नदाता से आत्मनिर्भर ऊर्जादाता बनाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सिंचाई क्षेत्र का रकबा निरंतर बढ़ रहा है। अभी 65 लाख हेक्टेयर है, इसे बढ़ाकर वर्ष 2028-29 तक 100 लाख हेक्टेयर तक लेकर जाएंगे।

किसानों को लौटाएंगे उनका वैभव
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि किसान कल्याण वर्ष में सरकार प्रदेश के किसानों के समग्र कल्याण के लिए हर जरूरी कदम उठाएगी। सालभर विभिन्न गतिविधियों के आयोजन के जरिए सरकार के 16 से अधिक विभाग/मंत्रालय आपसी समन्वय से किसानों को उनका वैभव लौटाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सोयाबीन के बाद अब सरसों की फसल को भी हम भावांतर योजना के दायरे में लेकर आएंगे। उन्होंने कहा कि कृषि आधारित उद्योगों के विकास में किसानों की भागीदारी बढ़ाई जाएगी। ऐसे उद्योग लगाने वालों को सरकार सब्सिडी देगी। प्रदेश में बीज परीक्षण कार्य से जुड़ी सभी प्रयोगशालाओं को और अधिक सशक्त कर सभी मंडियों का भी आधुनिकीकरण किया जाएगा। (शेष पृष्ठ 6 पर)

- मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य, जहां किसान कल्याण के लिए सालभर चलेंगी गतिविधियां
- 16 से अधिक विभाग समन्वय कर लाएंगे किसानों के लिए वैभव
- सोयाबीन के बाद अब सरसों में भी लागू होगी भावांतर योजना
- कृषि उद्योगों में किसानों की बढ़ाएंगे भागीदारी
- तीन साल में 30 लाख किसानों के खेतों में लगेंगे सोलर पम्प
- बीज परीक्षण प्रयोगशालाओं का किया जाएगा सुदृढ़ीकरण, सभी मंडियों का होगा आधुनिकीकरण
- माइक्रो इरीकेशन का बढ़ाया जाएगा दायरा
- फसल नुकसानी का आधुनिक तकनीक से होगा सर्वे
- तीन बड़ी नदी परियोजनाओं से 25 जिलों की 16 लाख हेक्टेयर भूमि होगी सिंचित
- किसानों के लिए जीरो प्रतिशत ब्याज की योजना रहेगी जारी
- किसानों की समृद्धि में ही है प्रदेश की समृद्धि
- मध्यप्रदेश देश का एकमात्र राज्य जहां खेती का रकबा 2.50 लाख हेक्टेयर बढ़ा
- किसान कल्याण वर्ष में सरकार के 10 संकल्प, प्राकृतिक एवं जैविक खेती को देंगे बढ़ावा
- शीघ्रनाशी फसलों वाले स्थानों पर बनाए जाएंगे फूड पार्क और फूड प्रोसेसिंग यूनिट
- कृषि उद्योगों के प्रोत्साहन देने सब्सिडी, सोलर सम्मेलन किए जाएंगे आयोजित
- डिंडोरी में बनेगा मध्यप्रदेश राज्य श्रीअन्न अनुसंधान केंद्र
- मुख्यमंत्री ने ई-विकास, वितरण एवं कृषि उर्वरक आपूर्ति समाधान प्रणाली ऐप का किया शुभारंभ
- किसान कल्याण वर्ष 2026 का हुआ भव्य शुभारंभ

1101 ट्रैक्टरों की ऐतिहासिक रैली के साथ कृषक कल्याण वर्ष 2026 का शुभारंभ

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने खुद ट्रैक्टर चलाकर दिया संवेदनशील नेतृत्व का संदेश
ट्रैक्टर चलाकर मुख्यमंत्री डॉ. यादव बने किसान

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राजधानी भोपाल को कृषक कल्याण वर्ष 2026 का भव्य एवं गरिमापूर्ण शुभारंभ किया। उन्होंने शुभारंभ अवसर पर किसानों की ऐतिहासिक 1101 ट्रैक्टरों की रैली का नेतृत्व किया। विशाल संख्या में ट्रैक्टरों की अनुशासित सहभागिता ने कार्यक्रम को ऐतिहासिक स्वरूप प्रदान किया। ट्रैक्टर रैली में किसानों के उत्साह को देखकर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि यह ट्रैक्टर रैली केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि किसानों की एकजुटता, आत्मविश्वास और प्रदेश सरकार की किसान-हितैषी सोच का सशक्त प्रतीक है। यह आयोजन इस बात का संकेत है कि राज्य सरकार कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए किसानों के हित में निरंतर और ठोस कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है।

कार्यक्रम में भावुक एवं प्रेरक क्षण तब आया, जब मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने स्वयं ट्रैक्टर की कमान संभाली। ट्रैक्टर चालक से आग्रह कर ट्रैक्टर पर बैठना और उसे चलाना मुख्यमंत्री की सहजत और किसानों के श्रम के प्रति सम्मान को दर्शाता है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव की इस सादागी और आत्मीयता ने उपस्थित जनसमुदाय को भावविमोदित कर दिया। किसानों ने तालियों की गड़गड़ाहट के



साथ किसान बने मुख्यमंत्री डॉ. यादव का अभिनंदन किया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सरकार की नीतियों का केंद्र किसान, नारी, युवा और गरीब हैं। इन चारों वर्गों के सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार योजनाओं और कार्यक्रमों का निर्धारण कर रही है, ताकि विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने वर्ष 2026 को "कृषक कल्याण वर्ष" के रूप में मनाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस दौरान किसानों के हितों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा। कृषक कल्याण वर्ष के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रदेश सरकार के 16 विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करेंगे, जिससे कृषि से जुड़े सभी आयाम—उत्पादन, लागत, विपणन, आय और कल्याण एक साथ

सुदृढ़ हो सकें।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि प्रदेश की कृषि विकास दर 16 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है, जो राज्य की कृषि क्षमता और नीतिगत प्रयासों की सफलता दर्शाती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार का लक्ष्य केवल उत्पादन बढ़ाना ही नहीं, बल्कि किसानों की आमदनी में वृद्धि और कृषि लागत में कमी लाने के लिए ठोस एवं व्यावहारिक उपायों को धरातल

पर उतारना है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि कृषि कल्याण वर्ष 2026 के संकल्प की पूर्ति का यह पहला दिन है। पूरे वर्ष विकास एवं मंगल कार्यक्रम निरंतर संचालित किए जाएंगे। सरकार का प्रयास रहेगा कि किसान समृद्ध हों, कृषि टिकाऊ बने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिले।

किसानों को अब ई-टोकन से मिलेगा खाद

इंदौर, राज्य शासन के निर्देशानुसार किसानों को सरल, सुलभ एवं रियल-टाइम पारदर्शिता के साथ उर्वरक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ई-विकास प्रणाली प्रारंभ की गई है। इस नवीन व्यवस्था के तहत किसानों को ई-टोकन के माध्यम से खाद का वितरण किया जाएगा।

इस प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर जिले में कृषि उत्पादन आयुक्त श्री अशोक वर्णवाल की अध्यक्षता में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में संभागीय संयुक्त संचालक कृषि, संभाग के समस्त उप संचालक कृषि, मार्कफेड एवं एम.पी. एग्रो के क्षेत्रीय प्रबंधक, जिला विपणन अधिकारी, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, सहकारी समितियों, विपणन समितियों एवं विपणन संघों से जुड़े गोदाम प्रभारी एवं ऑपरेटर उपस्थित रहे।

प्रशिक्षण के दौरान ई-टोकन प्रणाली के तकनीकी पहलुओं, आपूर्ति श्रृंखला



प्रबंधन तथा उर्वरक वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की प्रक्रिया पर विस्तृत जानकारी दी गई।

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के उप संचालक श्री सी.एल. केवड़ा ने बताया कि शासन द्वारा किसानों को समयबद्ध एवं पारदर्शी रूप से उर्वरक उपलब्ध कराने हेतु ई-टोकन एवं उर्वरक वितरण प्रणाली लागू की गई है। किसान अपनी सुविधा अनुसार स्वयं उर्वरक क्रय कर सकेंगे। इसके लिए किसान अपने मोबाइल के माध्यम से गूगल पर <https://etoken.mpkrisshi.org>

लिंक खोलकर आधार नंबर एवं ओटीपी के माध्यम से लॉग-इन कर ई-टोकन जारी कर सकते हैं।

लॉग-इन के बाद पोर्टल पर एग्री स्टैक (फार्मर आईडी) के माध्यम से कृषि भूमि स्वतः अपडेट हो जाएगी। किसान को मौसम एवं फसल का चयन करना होगा, जिसके आधार पर वैज्ञानिक पद्धति से आवश्यक उर्वरक की गणना पोर्टल पर स्वतः प्रदर्शित होगी। इसके बाद किसान सहकारी समिति की सदस्यता का चयन कर सकता है। पोर्टल पर मार्कफेड,

एम.पी. एग्रो, विपणन समिति एवं निजी उर्वरक विक्रेताओं के उपलब्ध स्टॉक की जानकारी प्रदर्शित होगी, जिससे किसान अपनी सुविधा अनुसार विक्रेता का चयन कर ई-टोकन जनरेट कर सकेगा।

ई-टोकन जारी होने के पश्चात किसान चयनित विक्रेता से तीन दिवस के भीतर उर्वरक क्रय कर सकता है। विक्रेता द्वारा मोबाइल ऐप से ई-टोकन स्कैन कर उर्वरक वितरण की पुष्टि की जाएगी। उर्वरक प्राप्ति के बाद किसान को भुगतान रसीद SMS एवं WhatsApp के माध्यम से प्राप्त

होगी। यदि तीन दिवस के भीतर खाद क्रय नहीं की जाती है, तो ई-टोकन स्वतः निरस्त हो जाएगा और पुनः नया टोकन जनरेट करना होगा।

जिले में इससे पूर्व समस्त पंजीकृत थोक एवं खुदरा उर्वरक विक्रेताओं को भी इस प्रणाली के संबंध में प्रशिक्षण दिया जा चुका है, जिसमें खुदरा स्तर पर ई-विकास प्रणाली के उपयोग, किसानों को सेवा प्रदान करने की प्रक्रिया एवं संभावित तकनीकी समस्याओं के समाधान पर मार्गदर्शन दिया गया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में उप संचालक कृषि श्री सी.एल. केवड़ा, सहायक संचालक कृषि श्री संदीप यादव, श्री विजय जाट, अनुविभागीय कृषि अधिकारी श्री शोभाराम एस्के एवं कृषि विकास अधिकारी श्री सी.एल. मालवीय भी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने बताया कि इस नवीन ई-विकास प्रणाली से उर्वरक वितरण में पारदर्शिता एवं दक्षता बढ़ेगी और किसानों को समय पर खाद की उपलब्धता सुनिश्चित होगी।

कृषि वर्ष-2026 में "समृद्ध किसान-समृद्ध प्रदेश" के लक्ष्य को करें साकार : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

तीन साल का लक्ष्य निर्धारित कर गतिविधियों की जाए संचालित

कृषि क्षेत्र में अनुसंधान, नवाचार, डिजिटल व्यवस्था सुनिश्चित कर प्रदेश के उत्पादों की राष्ट्रीय और वैश्विक उपस्थिति की जाए सुनिश्चित

किसान कल्याण और कृषि विकास से जुड़े सभी विभाग परस्पर समन्वय से करें कार्य

मुख्यमंत्री ने कृषि वर्ष-2026 में होने वाली गतिविधियों के संबंध में ली बैठक



भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि वर्ष-2026 को प्रदेश में कृषि वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। प्रदेश में विविध जलवायु जोन, पर्याप्त सिंचाई सुविधा, बेहतर रोड नेटवर्क उपलब्ध है। इसका लाभ लेकर किसानों की आय में वृद्धि और कृषि क्षेत्र में रोजगार सृजन के उद्देश्य आधारित गतिविधियां संचालित कर प्रदेश में "समृद्ध किसान-समृद्ध प्रदेश" के लक्ष्य को साकार किया जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने यह विचार आगामी कृषि वर्ष अंतर्गत कृषि और इससे जुड़े सहायक विषयों से संबंधित विभागों द्वारा तैयार की गई कार्य योजना की समत्व भवन (मुख्यमंत्री निवास) में समीक्षा के दौरान व्यक्त किए।

किसानों की आय में वृद्धि और रोजगार सृजन को प्रमुखता से लिया जाए

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि कृषि वर्ष-2026 में आरंभ की जा रही सभी गतिविधियां तीन साल का लक्ष्य निर्धारित कर संचालित की जाए। किसानों की आय में वृद्धि और रोजगार सृजन के लिए कृषि यंत्रिकरण, कृषकों के क्षमता विकास के लिए प्रशिक्षण और भ्रमण कार्यक्रम, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना, उद्यानिकी विस्तार, एफपीओ निर्माण आधारित गतिविधियों को प्रमुखता दी जाए। इसके साथ ही सस्ती ब्याज दरों पर ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए माइक्रो इरीगेशन, बेहतर बाजार नेटवर्क, किसानों को उनके उत्पाद का वाजिब मूल्य दिलवाने, पशुपालन तथा मछली पालन जैसी गतिविधियों के लिए कृषकों को प्रेरित करने जैसे प्रयास किए जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जलवायु के अनुकूल कृषि प्रबंधन, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, श्रीअन्न उत्पादन के प्रोत्साहन और जैव विविधता

तथा परम्परागत कृषि ज्ञान के संरक्षण और प्राकृतिक और जैविक खेती के लिए विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि कृषि क्षेत्र में अनुसंधान, नवाचार, डिजिटल व्यवस्था सुनिश्चित कर उनकी राष्ट्रीय और वैश्विक उपस्थिति सुनिश्चित की जाए।

किसानों को कृषि में उन्नत राज्यों और देशों की यात्रा कराये

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों में अन्य राज्यों में हो रहे सफल नवाचारों की जानकारी से किसानों को रू-ब-रू कराया जाए। इसके साथ ही किसानों को कृषि में उन्नत राज्यों और इजराइल तथा ब्राजील जैसे कृषि के क्षेत्र में नवाचार करने वाले देशों की यात्रा कराये। समृद्ध किसान-समृद्ध प्रदेश का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए किसान कल्याण, सहकारिता, पशुपालन एवं डेयरी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, राजस्व, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण, ऊर्जा, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा, मछुआ कल्याण और मत्स्य विकास तथा सिंचाई विभाग परस्पर समन्वय से कार्य करें।

प्रदेश के सभी जिलों में फूलों की खेती को करे प्रोत्साहित

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भोपाल में होने वाले गुलाब महोत्सव को पुष्प महोत्सव के रूप में आयोजित किया जाए। इसमें प्रदेश के विभिन्न जिलों में उत्पादित होने वाले अन्य फूलों को भी शामिल किया जाए तथा सभी जिलों में फूलों की खेती को प्रोत्साहित किया जाए। बैठक में बताया गया कि वर्ष-2028 का "इंटरनेशनल रोज कॉम्पीटिशन" भोपाल में होना प्रस्तावित है। यह भी बताया गया

कि सिंहस्थ : 2028 को देखते हुए उज्जैन जिले के 100 एकड़ क्षेत्र में फूलों की खेती को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में पराली निष्पादन के लिए हरसंभव प्रयास किए जाएं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि एफपीओ को दुग्ध उत्पादन गतिविधियों से भी जोड़ा जाए। बैठक में सहकारिता से कृषि क्षेत्र में आरंभ स्टार्ट अप को प्रोत्साहित करने की भी आवश्यकता बताई गई।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में कृषि वर्ष-2026 के अंतर्गत राज्य में होने वाले प्रस्तावित कार्यक्रम की जानकारी प्रस्तुत की गई।

जनवरी-2026

- नर्मदापुरम में कृषि आधारित कौशल विकास और कस्टम हायरिंग केन्द्रों का राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन।
- मंदसौर में सोयाबीन भावांतर भुगतान समापन तथा सोयाबीन के साथ मूंगफली और सरसों को योजना में शामिल करने के लिए भावांतर योजना विस्तार कार्यक्रम।
- भोपाल में गुलाब महोत्सव का आयोजन-पुष्प उत्पादक, निर्यातक और विशेषज्ञ सहभागिता करेंगे।

फरवरी-2026

- डिण्डौरी/उमरिया/मण्डला में कोदो-कुटकी बोनस वितरण कार्यक्रम के अंतर्गत मिलेट मेला, रोड शो, फूड फेस्टिवल, बायर-सेलर मीट और सेमिनार व कार्यशालाओं का आयोजन।
- निमाड़-मालवा क्षेत्र में राज्य स्तरीय एग्रीस्टेक एवं डिजिटल कृषि प्रदर्शनी का आयोजन।
- उज्जैन में गुलाब महोत्सव।
- भोपाल में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

समागम।

- ग्वालियर कृषि विश्वविद्यालय में कृषि, उद्यानिकी, मत्स्य, पशुधन और अन्य कृषि संबंधी क्षेत्रों में नवीन संभावनाओं पर कृषि मंथन और कृषि मेले का आयोजन।
- उज्जैन में राज्य स्तरीय सहकारिता सम्मेलन।

मार्च-2026

- प्राकृतिक खेती पर भोपाल में राष्ट्रीय संगोष्ठी, राज्य स्तरीय ट्रेड फेयर तथा बायर-सेलर मीट। संभाग स्तर पर भी प्राकृतिक खेती पर प्रदर्शनियां और सेमिनार होंगे।
- ग्वालियर में दुग्ध उत्पादकों का सम्मेलन। प्रत्येक दुग्ध संघ स्तर पर भी दुग्ध उत्पादकों का सम्मेलन होगा।
- इंदौर में पशुपालन पर कार्यक्रम।

अप्रैल-2026

- जबलपुर में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग समागम।

मई-2026

- सिवनी में धान महोत्सव तथा राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन।
- इंदौर/जबलपुर में कुक्कुट पालकों व उद्यमियों का सम्मेलन।
- इंदौर में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग समागम।

जून-2026

- भोपाल में राज्य स्तरीय आम महोत्सव।
- उज्जैन में राज्य स्तरीय कृषि उपज निर्यात प्रोत्साहन कार्यशाला।
- सागर में राज्य स्तरीय सोया महोत्सव तथा किसान सम्मेलन। इंदौर, उज्जैन और विदिशा में भी संभागीय आयोजन होंगे।
- उन्नत पशुपालन के लिए

पशुपालकों/ शासकीय प्रतिनिधियों का ब्राजील भ्रमण प्रस्तावित।

- अलीराजपुर में जिला स्तरीय आम महोत्सव।
- जबलपुर में राज्य स्तरीय सिंचाई और मखाना महोत्सव।

जुलाई-2026

- खरगोन, बड़वानी, धार, अलीराजपुर, खण्डवा पांडुर्ना तथा मालवांचल के जिलों में कपास और मिर्च महोत्सव तथा किसान सम्मेलन।
- नर्मदापुरम में कृषि आधारित कौशल विकास एवं कस्टम हायरिंग राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन।
- मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय जबलपुर में अन्तर्देशीय मत्स्य पालन और जलीय कृषि पर कार्यक्रम।
- बैतूल में जिला स्तरीय आम महोत्सव।
- नर्मदापुरम में सिंचाई और मखाना महोत्सव।

अगस्त-2026

- इंदौर में राज्य स्तरीय एफपीओ सम्मेलन। इसमें नवीन तकनीकों के ज्ञान, अवलोकन, विचार-विमर्श तथा प्रदर्शनी और विशेषज्ञों के विचारों को साझा करना शामिल होगा।
- भोपाल में राज्य स्तरीय केन्द्रीय गुणवत्ता प्रयोगशाला का लोकार्पण। इसका उद्देश्य मिलावटी दुग्ध व दुग्ध उत्पादों पर अंकुश लगाना, उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण उत्पाद उपलब्ध कराना है।
- राज्य के समस्त दुग्ध संघों के अंतर्गत "सांची है तो शुद्ध है" अभियान।
- भोपाल में 16 करोड़ रूपए लागत की दुग्ध उत्पादन निर्माण डेयरी का लोकार्पण।

सहकारिता में सीपीपीपी मॉडल से विकसित करें नए अवसर : मंत्री श्री सारंग

सहकारी बैंकों के सुदृढीकरण के लिये वैकल्पिक व्यवसाय मॉडल पर हो विचार

मंत्री श्री सारंग ने सभी सहकारी बैंकों के सीईओ से की वन-टू-वन चर्चा

भोपाल : सहकारिता मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने प्रदेश के सभी सीईओ से वन-टू-वन चर्चा कर बैंकों की कार्यप्रणाली, उपलब्धियों एवं चुनौतियों की विस्तृत समीक्षा की तथा भविष्य की कार्ययोजना के संबंध में आवश्यक दिशानिर्देश दिए। मंत्री श्री सारंग को अपेक्स बैंक, भोपाल में सहकारिता विभाग की गतिविधियों की समीक्षा की। बैठक में बताया गया कि पिछले 9 महीनों में सहकारी बैंकों के माध्यम से लगभग 50 हजार नए बचत खाते खोले गए हैं। वहीं 1 अप्रैल 2025 से 31 दिसंबर 2025 की अवधि में गत वर्ष की तुलना में 300 करोड़ रुपये अधिक ऋण वितरण किया गया है, जो सहकारी बैंकिंग व्यवस्था में बढ़ते विश्वास को दर्शाता है।

सीईओ से वन-टू-वन चर्चा कर बैंकों के सुदृढीकरण के लिए निर्देश

मंत्री श्री सारंग ने प्रदेश के सभी सहकारी बैंकों के सीईओ से वन-टू-वन चर्चा कर बैंकों के सुदृढीकरण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी सहकारी बैंकों के नोडल अधिकारियों को अपने-अपने जिलों में नियमित करें। जिन जिलों में कृषि क्षेत्र का विस्तार अधिक है वहां सहकारी बैंकों के सुदृढीकरण के लिए विशेष प्रयास करने को कहा। साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) वितरण एवं नई सदस्यता बढ़ाने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रत्येक बैंक को अपनी वर्क प्लानिंग रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए।

सीपीपीपी के माध्यम से विकसित करें नए अवसर

मंत्री श्री सारंग ने निर्देश दिए कि पारंपरिक बैंकिंग के साथ सहकारी बैंक अल्टरनेटिव बिजनेस मॉडल की ओर भी कदम बढ़ाएं। को-ऑपरेटिव पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (सीपीपीपी) के माध्यम से नए अवसरों एवं आय के नए आयाम विकसित किए जाएं।

लाभान्वित किसानों का करें प्रचार प्रसार

मंत्री श्री सारंग ने कहा कि जिन किसानों को सहकारी बैंकों के माध्यम से लाभ मिला है उनकी सफल कहानियों का सोशल मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, जिससे अन्य किसानों को भी सहकारी व्यवस्था से जुड़ने की प्रेरणा मिले और सरकार की योजनाओं का लाभ उठा सकें।



किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए सरकार प्रतिबद्ध

मंत्री श्री सारंग ने कहा कि पैक्स के कंप्यूटरीकरण से न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि सेवाएं भी तेज होंगी और किसानों को समय पर लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि तकनीक, नवाचार और पारदर्शिता के माध्यम से ही सहकारी संस्थाओं को आगे बढ़ाकर किसानों की आय में वृद्धि संभव है। राज्य सरकार सहकारी क्षेत्र को मजबूत कर किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए निरंतर

प्रतिबद्ध है। **जनवरी के अंत तक सभी पैक्स बनेंगी ई-पैक्स**

बैठक में बताया गया कि मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य होगा जो पैक्स के शत-प्रतिशत कंप्यूटरीकरण कार्य को पूर्ण करेगा। वर्तमान में प्रदेश की 2409 पैक्स ई-पैक्स में परिवर्तित हो चुकी हैं तथा शेष 2427 पैक्स को 31 जनवरी 2026 तक ई-पैक्स के रूप में परिवर्तित कर दिया जाएगा।

विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट कार्य

करने वाली सहकारी संस्थाओं को किया सम्मानित

मंत्री श्री सारंग ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों के ऋण उत्पादों के मूल्यांकन के लिये तैयार मैनुअल एवं भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के नवीन मास्टर परिपत्रों के संकलन से संबंधित पुस्तक का विमोचन किया। इसके साथ ही प्राथमिक सहकारी साख संस्था (पैक्स), राज्य के एक प्रमुख क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्राथमिक सहकारी समितियों (विपणन), प्राथमिक सहकारी संस्था (सहकारिता मंत्रालय की

पहला), प्राथमिक महिला सहकारी संस्था (महिला) एवं कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली समितियों को सम्मानित किया।

इस अवसर पर प्रमुख सचिव सहकारिता श्री डी.पी. आहूजा, आयुक्त सहकारिता श्री मनोज पुष्प, प्रबंध संचालक (अपेक्स बैंक) श्री मनोज गुप्ता सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी एवं प्रदेश भर के जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी उपस्थित रहे।

नाबार्ड प्रायोजित तीन दिवसीय बी-पैक्स प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न



सिवनी। भारत सरकार की राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा प्रायोजित सॉफ्ट कॉप (SOFT COP) योजना के अंतर्गत बी-पैक्स (बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख समितियों) के कर्मचारियों हेतु आयोजित तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफलतापूर्वक समापन हुआ। यह कार्यक्रम मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल के मार्गदर्शन में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, सिवनी के परिसर में आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य बी-पैक्स कर्मचारियों की व्यावसायिक दक्षता, प्रशासनिक क्षमता तथा सहकारिता से संबंधित नियमों की व्यवहारिक समझ को सुदृढ करना था। प्रशिक्षण में

भोपाल से पधारे वरिष्ठ एवं अनुभवी श्री के.पी. परिहार, श्री एस.के. जोशी तथा कोऑपरेटिव ट्रेनिंग सेंटर, जबलपुर से श्री वी.के. बर्बे द्वारा विभिन्न विषयों पर विस्तारपूर्वक मार्गदर्शन प्रदान किया गया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ माँ सरस्वती की पूजा-अर्चना एवं दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। उद्घाटन अवसर पर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, सिवनी के महाप्रबंधक श्री के.के. सोनी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। जिले की 35 बी-पैक्स समितियों के कर्मचारियों की प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई। साथ ही बी-पैक्स की उपविधियाँ, कार्यप्रणाली एवं मध्यप्रदेश सहकारिता नीति पर विस्तृत अध्ययन

कराया गया, जिससे प्रतिभागियों को सहकारी ढांचे की मूलभूत समझ प्राप्त हो सके। बी-पैक्स कर्मचारी सेवा नियम, केंद्रीय सहकारिता नीति, नीति निर्माण एवं निर्देशन में संचालक मंडल की भूमिका, उत्तरदायित्व एवं उसके महत्व पर गहन प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान व्याख्याताओं द्वारा व्यावहारिक उदाहरणों के माध्यम से समितियों के सुदृढ संचालन पर विशेष जोर दिया गया।

समितियों के व्यवसायिक संचालन में प्रभावी नेतृत्व की आवश्यकता एवं उसके महत्व पर विस्तार से चर्चा की गई। इसके उपरांत प्रतिभागियों की लिखित एवं मौखिक परीक्षा, प्रश्नोत्तर सत्र तथा फीड बैक लिया गया। कार्यक्रम के समापन अवसर पर सभी प्रतिभागियों को प्रशिक्षण

प्रमाण-पत्र वितरित किए गए तथा प्रशिक्षण को सफल बनाने में सहयोग देने वाले सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन किया गया। इस अवसर पर मध्यप्रदेश सहकारिता समिति कर्मचारी महासंघ, भोपाल की जिला इकाई सिवनी द्वारा प्रदेश कोषाध्यक्ष श्री रामकुमार बघेल, जिला अध्यक्ष श्री बंशी ठाकुर, जिला उपाध्यक्ष श्री सुदामा प्रसाद भारद्वाज, जिला पदाधिकारी श्री देवी प्रसाद सूर्यवंशी, श्री अरुण हिगे सहित समस्त कर्मचारियों ने अतिथियों का पुष्प गुच्छ से स्वागत किया। साथ ही भगवान श्री गणेश की प्रतिमा/सीनरी भेंटकर एवं मिठाई वितरण के माध्यम से सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित की गई।

किसानों को उपार्जन एवं खाद की उपलब्धता में दिक्कत न आए

काॅपरेटिव पब्लिक प्रायवेट पार्टनरशिप में जैविक खेती को बढ़ावा देने का कार्य किया जाए

भोपाल : सहकारिता व खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री विश्वास कैलाश सांरंग ने हरदा में आयोजित जिला विकास सलाहकार समिति की बैठक में कहा कि जिले में अनाज उपार्जन एवं खाद की उपलब्धता में किसानों को कोई अड़चन न आये। खनिज के अवैध उत्खनन व परिवहन को रोकने के लिये संयुक्त दल गठित कर अभियान चलाया जाए। श्री सांरंग ने कहा कि जिले में निर्मित हो रही सड़कों के निर्माण में अतिक्रमण आड़े न आये ऐसे अतिक्रमण को सख्ती से हटाया जाए। उन्होंने जिले में जैविक एवं प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के निर्देश देते हुए कहा कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, सहकारिता एवं कृषि विभाग के संयुक्त तत्वाधान में जैविक खेती के विकास के लिये कार्य किया जाए। साथ ही सहकारिता एवं पब्लिक प्रायवेट पार्टनरशिप के तहत भी जिले में जैविक खेती के विकास का कार्य हो।

मंत्री ने कहा कि जिला विकास सलाहकार समिति के गठन के पीछे शासन की मंशा विकास एवं कल्याण की योजनाओं में सेचुरेशन लाना, प्रशासकीय व्यवस्था का सुचारू संचालन के साथ-साथ विकास कार्यों में जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना है। समिति का उद्देश्य है कि सरकार की योजनाओं का सभी पात्र व्यक्तियों को लाभ मिले। साथ ही समिति के निर्णयों का अक्षरशः पालन हो। प्रत्येक विभाग का आमजन से जुड़े कार्य करने का प्रयास अच्छा होना चाहिए। बैठक में लोक निर्माण विभाग की समीक्षा के दौरान मंत्री द्वारा कहा गया कि जिले में स्वीकृत सड़कों के शेष निर्माण कार्यों को शीघ्रता से पूर्ण किया जाए। वनक्षेत्रों में निर्माणाधीन सड़कों भी समय सीमा में पूर्ण हो। उन्होंने कहा कि जिला अस्पताल के नवीन भवन प्रारम्भ होने के पूर्व वहां आवश्यक उपकरणों एवं संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में जल जीवन मिशन की पेयजल योजनाएं सुचारू रूप से संचालित हों। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की सड़कों के निर्माण एवं मरम्मत में देरी न हो। खाद्य विभाग अंतर्गत राशन प्राप्त करने वाले हितग्राहियों को राशन प्राप्त करने में असुविधा न हो। 80 वर्ष से उपर के हितग्राहियों को ई-केवायसी से मुक्त रखा जाए। इस दौरान जिले में जैविक खेती एवं जैविक हाट की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि जैविक खेती को सहकारिता एवं काॅपरेट के साथ जोड़कर जिले में जैविक खेती के विकास के क्षेत्र में नवाचार किया जाए। मंत्री ने कहा कि जिले के ज्यादा से ज्यादा



किसानों को जैविक खेती से जोड़ने के लिये जनजागरण अभियान चलाया जाए। मंत्री श्री सांरंग ने यह भी कहा कि सरकार की योजनाओं को आमजन तक पहुँचाने में जनप्रतिनिधियों का सहयोग लिया जाए एवं उनके आमजन के बीच सम्पर्कों का लाभ लिया जाए। मंत्री द्वारा शिक्षा, परिवहन एवं वेयरहाउसिंग विभाग की भी समीक्षा की गई। जल संसाधन विभाग की समीक्षा के दौरान टेल क्षेत्र के ग्रामों में सिंचाई जल की उपलब्धता की भी

जानकारी ली गई। श्री सांरंग ने कहा कि संबल योजना में पात्र हितग्राहियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के मामले लंबित न रहें। इस दौरान पूर्व कृषि मंत्री श्री कमल पटेल ने हरदा जिले को शतप्रतिशत सिंचित बनाने के लिये किये गये कार्यों की प्रदेश सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने हरदा लिफ्ट इरिगेशन परियोजना का नाम शहीद दीप सिंह चौहान रखने का बैठक में प्रस्ताव भी रखा, जिसको

अनुमोदित किया गया। उद्योग विभाग की समीक्षा के दौरान प्रभारी मंत्री द्वारा ऐसे उद्यमियों को ही जमीन आवंटित कराने के निर्देश दिये गये जो वास्तव में उद्योग चलायेंगे। उन्होंने कहा कि स्थानीय उत्पादकता पर आधारित उद्यमों की स्थापना को प्राथमिकता दी जाए। आदिम जाति कल्याण विभाग की समीक्षा के दौरान सभी पात्र हितग्राहियों को छात्रवृत्ति की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिये

गये। साथ ही कहा गया कि छात्रावासों में रह रहे विद्यार्थियों को कोई असुविधा न हो, यह ध्यान रखा जाए। वन विभाग की समीक्षा के दौरान वन क्षेत्रों में हुए पौधरोपण का भौतिक सत्यापन करने के लिये निर्देशित किया गया। पशुपालन विभाग के अधिकारी को निर्देश दिये गये कि दुग्ध समृद्धि सम्पर्क अभियान में जनप्रतिनिधियों को शामिल किया जाए। नये मिल्क रूट विकसित किये जायें एवं अधिक से अधिक दुग्ध समितियों का गठन हो। किसानों को ज्यादा से ज्यादा गौवंश के पालन के लिये प्रोत्साहित किया जाए।

विद्युत विभाग के अधिकारी को विद्युत की सुचारू आपूर्ति के लिये निर्देशित किया गया। यातायात व्यवस्था सुव्यवस्थित करने, रोड़ एक्सिडेंट रोकने तथा दुपहिया वाहन चालकों हेल्मेट लगाने के लिये जागरूक करने के भी प्रभारी मंत्री द्वारा निर्देश दिये गये।

कलेक्टर श्री सिद्धार्थ जैन द्वारा जिले में जैविक खेती के क्षेत्र में किये जा रहे कार्यों की बिन्दुवार जानकारी दी गई। इसके अलावा विभाग प्रमुखों द्वारा दो वर्ष में जिले में हुए विकास एवं उपलब्धियों से मंत्री को अवगत कराया गया।

दुग्ध संस्था पालखेड़ी में सहकारी सम्मेलन का आयोजन, सहकारी प्रदर्शनी एवं प्रचार-प्रसार कार्यक्रम का समापन



सीहोर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक एवं जिला सहकारी संघ मर्यादित, सीहोर के संयुक्त तत्वाधान में ग्राम पालखेड़ी स्थित दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था परिसर में सहकारी सम्मेलनका आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री कृपाल सिंह दुगारिया, जिला नोडल अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता श्रीमान सिंह परमार, अध्यक्ष, दुग्ध संस्था पालखेड़ी द्वारा की गई।

विशिष्ट अतिथियों में श्री मूलचंद वर्मा (पर्यवेक्षक, दुग्ध संघ), श्रीदिलीप सिंह परमार (उपाध्यक्ष), श्रीसुजान सिंह परमार (संस्था प्रबंधक) उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा माँ सरस्वती

के समक्ष दीप प्रज्ज्वलन कर किया गया। इस अवसर पर श्रीतेज सिंह ठाकुर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा नवम्बर 2024 में अंतरराष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन में वर्ष 2025 को अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया गया है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2025 के अंतर्गत सहकारिता के माध्यम से जनकल्याणकारी योजनाओं को जन-जन तक पहुँचाने, संस्थाओं को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने, उपविधियों में आवश्यक संशोधन करने तथा नवीन क्षेत्रों में सहकारी संस्थाओं के गठन के माध्यम से सदस्यों को आत्मनिर्भर बनाना प्रमुख उद्देश्य है। मुख्य अतिथि श्रीकृपाल सिंह दुगारिया द्वारा भोपाल दुग्ध सहकारी

संघ के माध्यम से संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि दुग्ध संघ द्वारा नवीन "मायरा योजना" प्रारंभ की गई है, जिसके अंतर्गत सदस्यों की कन्या के विवाह अवसर पर रु. 11,000/- की सहायता राशि एवं माँ-बेटी के वस्त्र भोपाल दुग्ध सहकारी संघ द्वारा प्रदान किए जाते हैं। साथ ही बीमा एवं पुरस्कार योजनाओं का लाभ लेने हेतु सदस्यों से आग्रह किया गया। इसके पश्चात बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, नापलाखेड़ी में दिनांक 30 एवं 31 दिसम्बर को आयोजित सहकारी प्रदर्शनी में-प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी संस्था, रेहटी; जागृति महिला बहुउद्देशीय संस्था, सीहोर; काष्ठकला सहकारी संस्था, बुधनी;

भोपाल दुग्ध संघ के सांची उत्पादों का विक्रय किया गया।

साथ ही बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, मोगराराम द्वारा संचालित जन औषधि केंद्र एवं इफको एम.सी. केंद्र की दवाइयों का भी विक्रय किया गया। दिनांक 31 दिसम्बर को सायं 4:00 बजे सहकारी प्रदर्शनी एवं सहकारी प्रचार रथ कार्यक्रम का विधिवत समापन किया गया। कार्यक्रम के अंत में श्री तेज सिंह ठाकुर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा सम्मेलन, प्रदर्शनी एवं प्रचार-प्रसार कार्यक्रम में उपस्थित समस्त अतिथियों, प्रतिभागियों एवं सहयोगी संस्थाओं के प्रति आभार व्यक्त किया गया।

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कृषक कल्याण वर्ष में किसानों का करेंगे समग्र कल्याण....

रिक्त पदों पर भर्ती कर कृषि तंत्र को करेंगे मजबूत

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि विभागीय अमले की तेज भर्ती के लिए भी हमारी सरकार प्रयासरत है। कृषि विभाग और राज्य कृषि विपणन (मंडी) बोर्ड में सभी श्रेणी के रिक्त पदों की जल्द से जल्द पूर्ति कर प्रदेश में कृषि तंत्र को और भी मजबूत बनाया जाएगा। सरकार माइक्रो इरिगेशन सिस्टम का दायरा बढ़ाने की ओर भी अग्रसर है। किसानों को होने वाली फसल नुकसानी का अब आधुनिक तकनीक से सर्वे कराया जाएगा। इससे किसानों को मुआवजे की राशि जल्द से जल्द मिल सकेगी। किसानों की बेहतरी और खुशहाली के लिए हर सभी कदम उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए जीरो प्रतिशत ब्याज दर से ऋण प्रदाय योजना आगे भी जारी रहेगी।

किसानों को मिलेगा

उनकी उपज और परिश्रम का बेहतर मूल्य

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि कृषक कल्याण वर्ष के दौरान कृषि आधारित उद्योगों के विकास के लिए सभी आवश्यक इंतजाम किए जाएंगे, ताकि किसानों को उनकी उपज एवं परिश्रम का बेहतर मूल्य मिल सके और गांवों में ही रोजगार के नए अवसर पैदा हों। इसके साथ ही प्रदेशभर में कृषि उत्सव और किसान मेलों का आयोजन कर किसानों को आधुनिक खेती के गुर सिखाए जाएंगे। प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने के साथ खेती-किसानी में नवाचारों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि खेतों में पसीना बहाने वाले किसान राष्ट्रसेवा का सर्वोच्च उदाहरण हैं। ऐसे में किसानों की सेवा, संबल और समृद्धि में सहयोग करना सरकार का कर्तव्य और धर्म है। उन्होंने प्रदेश के सभी किसानों से आह्वान करते हुए कहा कि वे नई तकनीकों को अपनाएं, बदलते समय के साथ कदम मिलाकर चलें और खेती को आधुनिक बनाएं। किसान कल्याण वर्ष का भव्य शुभारंभ कर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश के सभी अन्नदाताओं को भरोसा दिलाया कि किसानों की सुख-समृद्धि में ही सरकार का सुख है। हर कदम पर, हर जरूरत के वक्त सरकार किसानों के साथ खड़ी है।

अन्नदाता मध्यप्रदेश के

माथे का तिलक

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि अन्नदाता मध्यप्रदेश के माथे का तिलक है, जिसका तिलक खेत की मिट्टी है, वही मध्यप्रदेश का किसान है। उन्होंने कहा कि किसानों का पसीना प्रदेश की पहचान है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि कृषक कल्याण वर्ष के शुभारंभ के साथ हम आत्मनिर्भर और समृद्ध किसान, उन्नत कृषि और मूल्य श्रंखला आधारित

ग्रामीण अर्थव्यवस्था के माध्यम से समृद्ध प्रदेश का निर्माण करेंगे। किसानों की आय बढ़ाने और आय को स्थाई करेंगे, खेती को लाभ का धंधा बनाएंगे। तकनीक, नवाचार और वैज्ञानिक सोच से खेती को उन्नत करेंगे। उन्होंने कहा कि इस वर्ष हम कृषि आधारित उद्योग, फूड प्रोसेसिंग यूनिट को बढ़ावा देंगे। प्राकृतिक एवं जैविक कृषि को मिशन मोड में बढ़ावा देंगे। अपशिष्ट से बायोगैस, एथेनॉल और हरित ऊर्जा से किसान को ऊर्जादाता बनाएंगे। पर ड्रॉप मोर क्रॉप 2.0' और मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रदेश के कृषि उत्पादों के ब्रांडिंग की जाएगी, निर्यात पर विशेष फोकस होगा। रिसर्च, इनोवेशन के माध्यम से कृषिक सशक्तिकरण की दिशा में काम करेंगे। युवाओं को भी खेती से जोड़ेंगे। कृषि पर्यटन से गांवों में नए रोजगार और पहचान के अवसर पैदा होंगे। कृषि के साथ डेयरी, पशुपालन, मत्स्य पालन और खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर सहित फल, सब्जी मसाला एवं औषधीय फसलों के उत्पादन को भी मजबूती से बढ़ावा देंगे।

कृषि आधारित स्टार्ट-अप को देंगे बढ़ावा

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हम किसानों के जीवन में समृद्धि लेकर आएं। कृषि क्षेत्र में निवेश करने वाले उद्यमियों को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। कृषि आधारित स्टार्ट-अप को बढ़ावा देंगे। मेगा फूड पार्क, कृषि-प्रसंस्करण क्लस्टर और लॉजिस्टिक अधोसंरचना को सुदृढ़ करेंगे। 'खेत से फैक्ट्री तक' के विज्ञान के तहत किसानों को सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। खेत से लेकर बाजार तक किसान समर्थ, सक्षम और समृद्ध हों, यही हमारा एकमात्र लक्ष्य है।

किसान की मुस्कान ही मध्यप्रदेश की समृद्धि का आधार

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जिसका तिलक खेत की मिट्टी वो मध्यप्रदेश का किसान है। किसान भाइयो-बहनों के पसीने, धैर्य और अटूट परिश्रम से ही राज्य को देश की फूड बास्केट का मुकुट पहनाया है। आज हम कृषक कल्याण वर्ष 2026 का शुभारंभ कर रहे हैं। यह वर्ष मध्यप्रदेश के कृषि विकास और किसान कल्याण का इतिहास लिखेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि किसान भाईयों का सुख ही हमारा सुख है। किसान की मुस्कान ही मध्यप्रदेश की समृद्धि का आधार है।

किसान कल्याण के लिए सरकार के 10 संकल्प

मुख्यमंत्री ने डॉ. यादव ने बताया कि किसानों की आय बढ़ाने, लागत घटाने और खेती को स्थायी करने के लिए हमारी सरकार ने 10 दिशात्मक मॉडल तैयार किये हैं। यह मॉडल हमारे लिए 10

संकल्प की तरह हैं। इसके तहत हम कृषि बदलाव की बड़ी परियोजनाओं पर हम युद्ध स्तर पर काम करेंगे। किसानों की आय वृद्धि एवं वेस्ट में कमी लाने का पूरा प्रयास करेंगे। प्राकृतिक एवं जैविक कृषि को मिशन मोड पर बढ़ावा देंगे। संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए पर 'ड्रॉप मोर क्रॉप 2.0' और मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन को बढ़ावा देंगे। कृषि अपशिष्ट से ऊर्जा बनाने के लिए कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट (सीबीजी) की स्थापना की जाएगी। 'एमपी ग्लोबल एग्री ब्रांडिंग' और 'एग्री-हैकथॉन' जैसे नवाचारों पर विशेष फोकस करेंगे। प्रदेश के कृषि उत्पादों की ब्रांडिंग की जाएगी, निर्यात पर फोकस होगा। कृषि आधारित उद्योग और फूड प्रोसेसिंग यूनिट को बढ़ावा देंगे। रिसर्च, इनोवेशन एवं सशक्तिकरण की दिशा में काम किया जाएगा। युवाओं को खेती के लिए प्रेरित करेंगे। साथ ही आधुनिक तकनीक को खेती-किसानी का अहम हिस्सा बनाएंगे।

कृषक-कल्याण वर्ष का कैलेंडर हुआ जारी

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि कृषक कल्याण वर्ष 2026 के तहत सालभर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। फरवरी में कोदो-कुटकी बोनस वितरण, मार्च में प्राकृतिक खेती संगोष्ठी और मई में नर्मदापुरम का प्रसिद्ध 'आम महोत्सव' आयोजित किया जाएगा। अगस्त-सितम्बर में इंदौर में एफपीओ कन्वेंशन और छिंदवाड़ा में एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर निधि पर कार्यशालाएं होंगी। अक्टूबर और नवम्बर के महीने में 'फूड फेस्टिवल' और नरसिंहपुर में 'गन्ना महोत्सव' आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों की सुविधा के लिए हम सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी, बिजली, शून्य प्रतिशत ब्याज पर ऋण, फसलों पर समर्थन मूल्य और फसल बीमा की राशि का समय पर अंतरण किया जा रहा है। सरकार हर कदम पर किसानों के साथ है। किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम कृषक कल्याण वर्ष को सफल बनाएंगे।

प्रदर्शनी का शुभारंभ और कन्या-पूजन

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सम्मेलन स्थल पर आयोजित कृषि विकास प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। गौमाता पूजन एवं उन्हें रोटी खिलाकर सम्मेलन का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदर्शनी के हर स्टॉल में जाकर मुआयना किया और संबंधितों से चर्चा भी की। प्रदर्शनी में देशी-विदेशी नस्ल के गौवंश का अवलोकन किया। प्रदर्शनी में 65 प्रकार के उन्नत कृषि यंत्रों का प्रदर्शन किया गया। मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलित करने के साथ कन्या पूजन कर विशाल किसान सम्मेलन का विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं में

हितलाभ भी वितरित किये।

वरिष्ठ विधायक एवं प्रदेश अध्यक्ष श्री हेमंत खंडेलवाल ने प्रदेश के हर किसान परिवार की खुशहाली के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश के किसानों के उत्पाद अब निर्यात किए जाएंगे। वर्ष 2026 किसानों के कल्याण को समर्पित है। यह एक पुनीत संकल्प है। उन्होंने कहा टमाटर उत्पादन में हमारा प्रदेश, देश में प्रथम और गेहूं उत्पादन में दूसरे नम्बर पर है। यह एक बड़ी उपलब्धि है।

किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री एदल सिंह कंधाना ने कहा कि किसानों को मदद देकर मजबूत बनाना हम सबकी जिम्मेदारी है। इस वर्ष पूरी सरकार किसानों के कल्याण के लिए समर्पित होकर काम करेगी।

खेल एवं युवा कल्याण तथा

(पृष्ठ 3 का शेष)

कृषि वर्ष-2026 में....

सितम्बर-2026

- छिंदवाड़ा में कृषि अवसंरचना निधि योजना में लाभान्वित हितग्राहियों की राज्य स्तरीय कार्यशाला।
- सागर और रतलाम में एफपीओ सम्मेलन तथा स्किल डेवलपमेंट वर्कशॉप और क्रेडिट लिंकेज सेमिनार।
- उज्जैन में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रदेश में उत्कृष्ट कार्य करने वाले मैदानी कार्यकर्ताओं और पशुपालकों का सम्मान।
- बालाघाट में सिंचाई एवं मखाना महोत्सव।

अक्टूबर-2026

- भोपाल में पराली (फसल अवशेष) प्रबंधन पर कार्यशाला। जिला स्तर पर भी होंगे सम्मेलन।
- छिंदवाड़ा में एफपीओ सम्मेलन-मंडी बोर्ड तथा निजी संस्थाओं के साथ बायर-सेलर मीट।
- इंदौर में जलीय कृषि विपणन संगोष्ठी।
- नर्मदापुरम में कृषि आधारित कौशल विकास और कस्टम हायरिंग पर राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन।
- इंदौर में राज्य स्तरीय सब्जी महोत्सव। जिला स्तर पर भी होंगे कार्यक्रम।
- जबलपुर में राज्य स्तरीय सहकारिता सम्मेलन। डिजीटल सेवाओं के विस्तार पर केन्द्रित होगा सम्मेलन।

नवम्बर-2026

- नरसिंहपुर में राज्य स्तरीय गन्ना महोत्सव।
- राजगढ़ में जिला स्तरीय सब्जी महोत्सव।
- भोपाल में राज्य स्तरीय सहकारिता सम्मेलन। डिजीटल समावेशन और कृषकों की सदस्यता का विस्तार होगा लक्ष्य। जिला स्तर पर भी होंगे कार्यक्रम।

मंडी आधुनिकीकरण के परिणामस्वरूप साफ, ग्रेडेड

सहकारिता मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा कि हमारी सरकार अन्नदाताओं के साथ है। किसान की खेती-किसानी को बेहतर बनाकर पैदावार एवं आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार के 16 से अधिक विभाग मिलकर काम करेंगे। यह एक लक्ष्य की साधना का वर्ष है और हम यह संकल्प पूरा करके रहेंगे।

पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती कृष्णा गौर ने स्वागत उद्बोधन देते हुए कहा कि किसान ही प्रदेश की सुख-समृद्धि, सुरक्षा और विकास का द्वार है। किसानों से ही प्रदेश समृद्ध होगा। खेत से बाजार तक और बीज को ब्रांड बनाने तक सरकार किसानों के साथ है। यह वर्ष किसान कल्याण के मामले में मील का पत्थर साबित होगा।

और पैकड उपज से प्रदेश के कृषि उत्पादों की राष्ट्रीय बाजारों में बढ़ेगी भागीदारी

बैठक में बताया गया कि मंडियों के आधुनिकीकरण के लिए भी गतिविधियां संचालित की जाएंगी। वर्ष 2025-26 में 20, वर्ष 2026-27 में 19 और वर्ष 2027-28 में 42 मंडियों को eNAM मंडियों के रूप में विकसित करने का लक्ष्य है। उल्लेखनीय है कि eNAM या राष्ट्रीय कृषि बाजार भारत में कृषि वस्तुओं के लिए एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। मंडियों के आधुनिकीकरण से साफ, ग्रेडेड और पैकड उपज के कारण उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार होगा और प्रदेश के कृषि उत्पादों की राष्ट्रीय बाजारों में भागीदारी में बढ़ोत्तरी होगी। इससे किसानों को बेहतर एवं प्रतिस्पर्धी मूल्य प्राप्त होंगे तथा किसानों की आय में वृद्धि सुनिश्चित की जा सकेगी। बैठक में बताया गया कि मंडियों में पारदर्शी नीलामी, अनियमितताओं की रोकथाम, पुराने प्रांगणों को व्यवस्थित करने, अतिक्रमण से संभावित क्षति को रोकने और नवाचार करते हुए दक्षता संवर्धन के प्रयास किए जाएंगे। कृषि अवसंरचना निधि (एआईएफ) योजना में भारत सरकार के सहयोग से प्रदेश में फसलोत्तर प्रबंधन, अवसंरचनाओं और कृषि परिसंपत्तियों के निर्माण और विकास के लिए भी गतिविधियां संचालित की जाएंगी।

समीक्षा बैठक में सहकारिता मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाह, मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन, अपर मुख्य सचिव श्री अशोक बर्णवाल, अपर मुख्य सचिव श्री अनुपम राजन, अपर मुख्य सचिव श्री रश्मि अरूण शर्मा, प्रमुख सचिव श्री डी.पी. आहूजा, प्रमुख सचिव श्री उमाकांत उमराव, सचिव किसान कल्याण तथा कृषि विकास श्री निशांत वरवडे सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

बी-पैक्स प्रबंधकों एवं कंप्यूटर ऑपरेटरों हेतु दो दिवसीय कौशल उन्नयन एवं नेतृत्व विकास कार्यक्रम संपन्न

बड़वानी। मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल एवं जिला सहकारी संघ मर्यादित, खरगोन के संयुक्त तत्वावधान में बड़वानी स्थित बी-पैक्स परिसर में जिले की पैक्स संस्थाओं के समिति प्रबंधकों एवं कंप्यूटर ऑपरेटरों के लिए आयोजित दो दिवसीय कौशल उन्नयन एवं नेतृत्व विकास कार्यक्रम का सफलता पूर्वक आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला सहकारी संघ मर्यादित, खरगोन के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री ओंकार यादव, शाखा प्रबंधक श्री संजय शर्मा, श्री राजेश पाटीदार, सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र, इंदौर से जिला सहकारी प्रशिक्षक श्री सुयश शर्मा, तथा विभिन्न पैक्स संस्थाओं के प्रबंधक एवं कंप्यूटर ऑपरेटर उपस्थित रहे। इस अवसर पर वक्ताओं द्वारा सहकारी संस्थाओं में दक्ष प्रबंधन, नेतृत्व क्षमता विकास, तकनीकी ज्ञान एवं कार्यक्षमता में वृद्धि जैसे विषयों पर विस्तार पूर्वक मार्गदर्शन प्रदान किया



जिला सहकारी संघ मर्यादित, खरगोन के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री ओंकार यादव, बड़वानी शाखा प्रबंधक श्री राजेश पाटीदार, संधवा शाखा प्रबंधक

श्री हितेश पाटीदार, सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र, इंदौर से जिला सहकारी प्रशिक्षक श्री सुयश शर्मा, सहित जिले की विभिन्न पैक्स संस्थाओं के प्रबंधक एवं कंप्यूटर

ऑपरेटर उपस्थित रहे।

इस दौरान वक्ताओं द्वारा प्रतिभागियों को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं नियमों की विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही प्रभावी नेतृत्व, कार्यक्षमता में वृद्धि, कार्यालयीन प्रबंधन, डिजिटल कार्यप्रणाली तथा सहकारी संस्थाओं के सुदृढ़ एवं पारदर्शी संचालन से संबंधित विषयों पर व्यावहारिक उदाहरणों के माध्यम से मार्गदर्शन प्रदान किया गया। कार्यक्रम के अंत में प्रतिभागियों के साथ संवाद एवं अनुभव साझा किए गए। प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण को अत्यंत उपयोगी एवं ज्ञानवर्धक बताते हुए इस प्रकार के कौशल विकास कार्यक्रमों को नियमित रूप से आयोजित करने की आवश्यकता पर बल दिया। आयोजन की सफलता पर आयोजक संस्थाओं द्वारा उपस्थित अतिथियों, प्रशिक्षकों एवं प्रतिभागियों के प्रति आभार व्यक्त किया गया।

नाबार्ड प्रायोजित छः दिवसीय सॉफ्टकॉब प्रशिक्षण संपन्न



पन्ना। नाबार्ड द्वारा प्रायोजित सॉफ्टकॉब योजना अंतर्गत छह दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन दिनांक 5 से 10 जनवरी 2026 तक जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, पन्ना के सभागृह में किया गया। इस प्रशिक्षण में पन्ना जिले की एम-पैक्स संस्थाओं के 30 समिति प्रबंधकों ने सहभागिता की। कार्यक्रम का शुभारंभ बैंक के प्रभारी सीईओ श्री अमित श्रीवास्तव, सहकारिता विभाग की वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक श्रीमती अर्चना गुप्ता एवं सहकारी प्रशिक्षण केंद्र नौगांव के प्राचार्य श्री शिरीष पुरोहित

द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को पैक्स की आदर्श उपविधियाँ, लेखा संधारण, वसूली प्रबंधन, सहकारिता नीति, बीमा योजनाएँ, ईआरपी सॉफ्टवेयर, इफको के नैनो उत्पाद, एकीकृत फसल प्रबंधन तथा साइबर सुरक्षा जैसे विषयों पर जानकारी दी गई।

नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक श्री विवेक गुप्ता, इफको के फील्ड मैनेजर श्री राजेश मौर्य, कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ तकनीकी सहायक श्री रितेश बागोरा, जिला सहकारी संघ

पन्ना के विकास अधिकारी श्री योगेश पांडे सहित विभिन्न विषय विशेषज्ञों ने प्रशिक्षण सत्रों को संबोधित किया। सहकारी प्रशिक्षण केंद्र नौगांव के प्राचार्य श्री शिरीष पुरोहित एवं प्रशिक्षक श्री बाबूलाल कुशवाहा ने प्रशिक्षण में सक्रिय भूमिका निभाई। अंतिम दिवस बैंक के सीईओ श्री एस. के. कनोजिया द्वारा आगामी कार्ययोजनाओं की जानकारी दी गई। समापन अवसर पर प्रतिभागियों से फीडबैक लिया गया, एग्जिट टेस्ट आयोजित हुआ तथा प्रशिक्षण प्रमाणपत्र



वितरित किए गए। प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण को उपयोगी बताते हुए नाबार्ड

एवं आयोजक संस्थाओं के प्रति आभार व्यक्त किया।

नाबार्ड प्रायोजित सॉफ्टकॉब योजनान्तर्गत बी-पैक्स कार्मिकों का तीन दिवसीय प्रशिक्षण सम्पन्न



छिंदवाड़ा। नाबार्ड द्वारा प्रायोजित सॉफ्टकॉब प्रशिक्षण सहायता योजना के अंतर्गत बी-पैक्स (प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों) के कार्मिकों के लिए तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, छिंदवाड़ा में दिनांक 05 जनवरी से 07 जनवरी 2026 तक किया गया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य बी-पैक्स कार्मिकों की कार्यक्षमता, नेतृत्व क्षमता एवं सहकारी प्रबंधन कौशल को सुदृढ़ करना रहा। प्रशिक्षण के दौरान सहकारी अधिनियम, लेखा-जोखा, बैंकिंग प्रक्रियाएं, सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग, ऋण वितरण एवं वसूली, शासन की सहकारी योजनाएं तथा समिति प्रबंधन से

संबंधित विषयों पर विस्तार से मार्गदर्शन प्रदान किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में श्री वी.के. बर्वे, प्राचार्य, सहकारी प्रशिक्षण केंद्र द्वारा प्रमुख प्रशिक्षक के रूप में मार्गदर्शन प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त श्री पी.के. परिहार, सेवानिवृत्त महाप्रबंधक तथा श्री श्रीकुमार जोशी, सेवानिवृत्त

संयुक्त संचालक, सहकारिता द्वारा अपने दीर्घकालीन अनुभवों के आधार पर सहकारिता, वित्तीय अनुशासन एवं प्रभावी समिति संचालन पर व्यावहारिक जानकारी साझा की गई। कार्यक्रम के समाधान किया गया तथा समापन अवसर पर अपेक्षा व्यक्त की गई कि बी-पैक्स

कार्मिक प्रशिक्षण से प्राप्त ज्ञान को अपनी-अपनी समितियों में व्यवहार में लाकर सहकारी संस्थाओं को और अधिक सशक्त बनाएंगे। इस अवसर पर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अधिकारीगण, प्रशिक्षण समन्वयक एवं बड़ी संख्या में बी-पैक्स कार्मिक उपस्थित रहे।

इंदौर सहकारी प्रशिक्षण केंद्र में 15 दिवसीय अल्पकालिक इंटरशिप (सत्र-2) का शुभारंभ



इंदौर। सहकारी प्रशिक्षण केंद्र इंदौर में 15 दिवसीय अल्पकालिक इंटरशिप कार्यक्रम (सत्र क्रमांक-2) का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ केंद्र के प्राचार्य श्री दिलीप मरमठ द्वारा किया गया। उद्घाटन अवसर पर उन्होंने प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि सहकारिता क्षेत्र में सैद्धांतिक ज्ञान के साथ-साथ व्यावहारिक अनुभव अत्यंत आवश्यक है, जिससे युवाओं को भविष्य में रोजगार एवं नेतृत्व के बेहतर अवसर प्राप्त होते हैं। श्री मरमठ ने बताया कि यह इंटरशिप कार्यक्रम प्रतिभागियों को सहकारी संस्थाओं की कार्यप्रणाली, प्रबंधन, लेखांकन, सदस्य सेवाएँ, शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन तथा व्यावहारिक फील्ड अनुभव से परिचित कराने हेतु आयोजित किया

गया है। कार्यक्रम के अंतर्गत प्रतिभागियों को कक्षा आधारित प्रशिक्षण के साथ-साथ केस स्टडी, समूह चर्चा एवं व्यावहारिक अभ्यास भी कराया जाएगा। प्रशिक्षण केंद्र प्रबंधन द्वारा जानकारी दी गई कि कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं में सहकारिता के प्रति रुचि विकसित करना, उनके कौशल का उन्नयन करना तथा उन्हें सहकारी क्षेत्र में करियर के लिए तैयार करना है। कार्यक्रम में विभिन्न जिलों से आए प्रतिभागी सम्मिलित हो रहे हैं, जो आगामी 15 दिनों तक नियमित रूप से प्रशिक्षण गतिविधियों में भाग लेंगे। कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु प्रशिक्षण केंद्र की ओर से समुचित व्यवस्थाएँ की गई हैं तथा प्रतिभागियों को अनुशासन, समयबद्धता एवं सक्रिय सहभागिता के लिए प्रेरित किया गया।

शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई स्नातकोत्तर महाविद्यालय में 15 दिवसीय अल्पकालिक इंटरशिप (सत्र-1) के प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित



इंदौर। शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई स्नातकोत्तर महाविद्यालय (न्यू जी.डी.सी.), इंदौर में 15 दिवसीय अल्पकालिक इंटरशिप कार्यक्रम (सत्र क्रमांक-1) के प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। यह कार्यक्रम महाविद्यालय परिसर में आयोजित किया गया। प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम में इंदौर सहकारी प्रशिक्षण केंद्र के प्राचार्य श्री दिलीप मरमठ उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई स्नातकोत्तर महाविद्यालय के अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण भी उपस्थित रहे। अपने संबोधन में श्री

मरमठ ने कहा कि इस प्रकार के इंटरशिप कार्यक्रम विद्यार्थियों को सहकारिता, प्रबंधन एवं प्रशासनिक कार्यप्रणाली का व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करते हैं, जिससे वे भविष्य की चुनौतियों के लिए बेहतर रूप से तैयार हो पाते हैं। उन्होंने सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण करने वाले सभी प्रतिभागियों को बधाई एवं शुभकामनाएँ दीं। महाविद्यालय प्रशासन ने भी इस कार्यक्रम को विद्यार्थियों के कौशल विकास एवं रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण की दिशा में एक सराहनीय पहल बताया।